International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र :- एक अवलोकन

डॉ रमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर[1],

विजय दीक्षित, रिसर्च स्कॉलर[2]

हरियाणा केन्दीय विश्वविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग

प्रस्तावना :-

भारतीय समाज प्राचीन काल से ही समृद्ध एवं आत्मनिर्भर रहा है। भारतीय चिंतको ने आत्मनिर्भरता पर अपने विचार प्रस्तुत किए है। गाँधी जी की आत्मनिर्भरता की संकल्पना सबसे प्रासंगिक है और तत्कालीन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आधार प्रस्तुत करती है। सभी राष्ट्रो के लिए रक्षा क्षेत्र हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है,रक्षा को समझने के विभिन्न आयाम एवं नजरिये है इसको सिर्फ सैन्य एवं हथियार सम्बन्ध में नहीं देख सकते हैं। हाल ही में विश्व कोरोना काल के संकट का सामना कर रहा है, जहां भारत इस आपदा में भी अपने विकास एवं स्वावलम्ब के नए नए रास्ते ढूंढ रहा है। उन्ही रास्तो में प्रमुख है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। जिसमे भारत अपने देशीय उत्पादों को प्रमुख महत्व देता है और रक्षा क्षेत्र भी आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ है, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देशीय नीति के माध्यम से इसमें सुधार है। वैश्वीकरण में जहाँ सभी देश एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है,वहीं सीमित संसाधन होने की वजह से भारत के सामने चुनौतियाँ भी है। वो इन संकटो से कैसे आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना बढ़ाते है? एवं रक्षा सुधारो में किस प्रकार देशीय नीति एवं सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है? इस शोध पेपर में प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत का प्रयोग किया गया है। इस शोध पेपर का प्रमुख लक्ष्य भारत में आत्मनिर्भरता के सन्दर्भ में रक्षा क्षेत्र का अवलोकन करना है।

मुख्य बिंदु :- आत्मनिर्भर भारत , मेक इन इंडिया ,कोविड 19 ,रक्षा क्षेत्र ,रक्षा उद्योग, वैश्वीकरण ।

परिचय

कोरोना वैश्विक महामारी ने दुनिया भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, शासन प्रणालियों, और भू-राजनीतिक संघर्षों की विफलताओं को उजागर करने वाली दुनिया की दुखद झांकी को प्रस्तुत किया है। जिसने राष्ट्रों के बीच एवं भीतर नए संघर्षों को गति दी है। इस स्थिति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने प्रतिकूल प्रभावों को काफी हद तक सीमित करने में सक्षम रहा है। फिर भी भारत में आर्थिक विकास का पतन हुआ और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों और श्रमिकों का अभूतपूर्व प्रवास भी हुआ। लेकिन जैसा कि कई आर्थिक विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि औसतन यह कहना गलत होगा कि भारत अपनी पिछले वर्ष के आर्थिक विकास दर को बहाल नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संघचालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों (आरएसएस के स्वयंसेवकों) को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटना सभी भारतीयों के सामूहिक परिश्रम से ही संभव है। उन्होंने कहा कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सभी भारतीय सामूहिक रूप से COVID 19 के खिलाफ लड़ेंगे और इस प्रकार आरएसएस का दृष्टिकोण पीएम मोदी के साथ पारस्परिक रूप से सुसंगत है और संगठन सभी सरकारी प्रयासों का पूरे दिल से समर्थन करेगा। उन्होंने सभी भारतीयों से स्वदेशी संसाधनों और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने के अपने प्रयासों मे वृद्धि करने का भी आग्रह किया। रक्षा क्षेत्र में इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक स्वदेशी विनिर्माण पर जोर देती है और आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देती है। इसमें

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

नीतिगत संशोधन मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने की दिशा में एक सही कदम है। यह रक्षा उत्पादन और भारत को रक्षा उपकरणों का निर्यातक बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है जो स्थापित वैश्विक बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। प्रधानमंत्री के अनुसार हमारा उद्देश्य रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना,नई तकनीक विकसित करना और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका देना है। जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले और मेक इन इंडिया की संकल्पना पूरी हो सके।

आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा

पीएम मोदी ने 12 मई, 2020 को देश को अपने संबोधन में "आत्मनिर्भर भारत या स्वाबलम्बी भारत " बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भारता के महत्व को समझाया और कहा कि जब दुनिया संकट में है तो हमें एक प्रतिज्ञा करनी होगी जो इस वैश्विक संकट से बड़ी है वो प्रतिज्ञा ये है की हमें 21 वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और ऐसा करने का तरीका देश को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम मोदी ने कहा आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत आत्म-केंद्रित होने की बात कर रहा है यह एक अलग अवधारणा है। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल मे देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ रुपये जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर है उस विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह घोषणा गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए बनायी गयी जो कोरोना महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह अवधारणा लोकल के लिए वोकल बने रहने पर जोर देती है। इस योजना मे रक्षा क्षेत्र मे सुधार एवं आत्मनिर्भर संकल्पना प्रस्तुत की गयी है, जिसमे स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी तथा देश को उत्पादन के मामले में स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमे हथियारों व प्लेटफार्मों की एक सूची जारी की जाएगी जो एक वर्ष के समय पर आधारित आयात के लिए प्रतिबंधित होंगे। इसके अलावा सरकार ने योजना बनाई है उसमे अतिरिक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के जरिए ऑर्डिनेंस सप्लाई में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने की योजना बनाई है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता रक्षा एवं सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में ताकत बढ़ाने से एवं विश्व के साथ काम करने की शर्तें नए सिरे से तैयार करने से बनेगा।

27 अगस्त 2020 को आत्मानिर्भरता डिफेंस इंडस्ट्री आउटरीच वेबिनार नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ाना एवं आत्मानिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भरता के लिए हमारा संकल्प' भारत के भीतर तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत को सक्षम बनाने और वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए है। इसके माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता होने की देश की क्षमता को बढ़ावा देगा। 101 वस्तुओं को घरेलू खरीद के लिए निर्धारित करने जैसे प्रयासो से घरेलू खरीद को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू रक्षा उद्योगों में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार द्वारा घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए नीतिगत बदलावों एवं निर्यात को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है। उनके अनुसार सरकार 2025 तक रक्षा विनिर्माण में 1.75 लाख करोड़ रुपये (25 बिलियन डॉलर) के कारोबार का लक्ष्य बना रही है क्योंकि रक्षा क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारतीय चिंतन में आत्मनिर्भरता का सिद्धांत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया आह्वान आत्मनिर्भरता के विचार को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम विभिन्न भारतीय चिंतको के चिंतन में इसके महत्व को देखते है। स्वदेशी एवं देशीय की प्रथम अवधारणा स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारो में मिलती है। दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में स्वराज,स्वदेशी, राष्ट्रवाद ,लोकसत्ता ,प्रजातंत्र पर आधारित राज्यशासन की अवधारणा प्रस्तुत की है जिन पर किसी भी तरह के पश्चिमी चिंतन एवं दर्शन का प्रभाव नहीं पड़ा है एवं उनका सम्पूर्ण चिंतन भारतीय वैदिक दर्शन पर आधारित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले पंडित बिशन नारायण ने बताया की दयानंद सरस्वती अपने युग के सर्वाधिक मौलिक हिंदू हैं एवं वही प्रथम भारतीय सुधारक हैं जिन्होंने पश्चिमी संस्कृति से कुछ ना ग्रहण करते हुए भारतीय वैदिक संस्कृति पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत प्रस्तुत किए एवं स्वराज की संकल्पना दी। वही दयानंद सरस्वती की जीवनी के अंग्रेजी लेखक शिवनंदन प्रसाद कुल्यार ने बताया की दयानंद सरस्वती भारत में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान के दिशा निर्देश उस समय दिए जब भारत में इसकी कोई चर्चा ही नहीं थी। स्वराज के लिए वह कितने उत्सुक थे इसका अंदाजा उनकी प्राथना पुस्तक से लगाया जा सकता है जिसमे वह परमात्मा से देश की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता की याचना करते है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि कोई कितना ही करें किंतु स्वदेशी राज्य ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि होता है इस आधार पर दयानंद सरस्वती जी ने भारत में स्वराज ,स्वतंत्रता,स्वाबलम्ब,आत्मनिर्भरता की सर्वप्रथम अवधारणा प्रस्तुत की।

दूसरी अवधारणा बाल गंगाधर तिलक के चिंतन में मिलती है जहां बाल गंगाधर तिलक ने कहा, "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको में लेकर रहूँगा" तिलक के ये विचार उपनिवेशवादी शासन के विरोध में एवं भारतीय वैदिक दर्शन के समर्थन में थे। तिलक के ये विचार सम्पूर्ण भारत में जंगल की आग की तरह फैले जो गुलाम भारतीयों में ऊर्जा का संचार करती है। इन्होने भारत के लिए स्वदेशी की अवधरणा पर बल दिया।

स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत इसकी जीवनशैली का वर्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक दत्तोपंत ठेंगडी द्वारा किया गया है। जो शायद इसके सबसे दृढ़ आर्थिक सिद्धांतकार थे। दत्तोपंत ठेंगडी एक संघ विचारक स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ के संस्थापक भी थे। अपनी कृति "द थर्ड वे " में उन्होंने कहा कि स्वदेशी की भावना देशभक्ति की बाहरी और व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। उनके लिए देशभक्ति, किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए देशभक्त अवधारणा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ असंगत नहीं हैं, बशर्ते कि उत्तरार्द्ध हर देश के स्वाभिमान के लिए उचित सम्मान के साथ समान पायदान पर हो। पुस्तक का महत्वपूर्ण तर्क आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता सुझाता है जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद के पहले से मौजूद सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं है। थेंगडी ने तर्क दिया कि विश्व साम्यवाद लगभग ध्वस्त हो गया था और यह पूंजीवाद गिरावट पर था। लेकिन इसके निधन में देरी हो रही थी। उन्होंने लिखा कि विश्व सिद्धांतकारों ने 'तीसरे विकल्प' के लिए अपनी खोज शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा, "कोई भी वस्तुगत परिवर्तन तब तक प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता जब तक कि यह एक उपयुक्त व्यक्तिपरक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से पहले और आगे न बढ़े। उनके विचार में,थर्ड वे के पीछे का विचार न तो पूंजीवाद के व्यक्तिवादी लोकाचार में निहित था और न ही

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

साम्यवाद के सामूहिक आग्रह में, बल्कि इसने एक ऐसे दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें समाज सामूहिक रूप से भौतिक और गैर-भौतिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इसी रूपरेखा में, इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम: द हिंदू व्यू, नामक पुस्तक में आगे तर्क दिया कि यूरोकेन्द्रवाद इतिहास के वर्तमान संस्करण को छोड़ना अपरिहार्य है,जो अनुपात की भावना से रहित है,और ऐतिहासिक जांच के एक नए चरण की शुरुआत करता है। एक नया ढांचा,संदर्भ की नई शर्तें, मूल्यों का एक नया पैमाना, जो वैश्वीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि धर्म का हिंदू सिद्धांत एक ऐसी अर्थव्यवस्था को डिजाइन करने के लिए सबसे अच्छे मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है जो सामूहिक खुशियों के आदर्श पर जोर दे रही है न की केवल अथक, भौतिक समृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धी दौड़ पर।

महात्मा गांधी ने अपनी कृति हिन्द स्वराज में स्वराज एवं आत्मनिर्भर स्वाबलंबी भारत अवधारणा प्रस्तुत की है। गांधीजी भारतीय गांवों और उनकी पंचायती व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में थे। आदर्श ग्राम की अवधारणा सबसे पहले महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तावित की गयी थी। एक आदर्श गाँव के बारे में उनकी दृष्टि स्पष्ट और क्रमबद्ध थी। एक आदर्श गाँव जिसे आज मॉडल गाँव के रूप में भी देखते है वह इन अपेक्षाओ के लिए प्रेरित और विकसित होने की उम्मीद करता है। एक गाँव जिसमे पर्याप्त बुनियादी जरूरतों और सुविधाए है जो इसे विकसित करने और दूसरे गाँव को प्रेरित करने के लिए एक मॉडल गाँव में बदल सकते है। गाँधी जी द्वारा एक आदर्श गाँव पर इनके विचार हरिजन में व्यक्त किये गए है जो इस प्रकार है की " एक आदर्श एवं आत्मनिर्भर भारतीय गाँव का निर्माण किया जाएगा ताकि वह खुद को संपूर्ण स्वच्छता के लिए उधार दे सके। इसमें पांच मील की परिधि में प्राप्य सामग्री से निर्मित पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन के साथ कॉटेज होंगे। कॉटेज में घर के उपयोग के लिए और अपने मवेशियों को घर में रखने के लिए घरवालों को सक्षम करने वाले आंगन होंगे। गाँव की गलियाँ और गलियाँ सभी टालने योग्य धूल से मुक्त होंगी। इसकी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कुएँ होंगे और सभी के लिए सुलभ होगा। इसमें सभी के लिए पूजा के घर होंगे, एक आम सभा स्थल, अपने मवेशियों को चराने के लिए एक गांव, एक सहकारी डेयरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जिसमें औद्योगिक शिक्षा केंद्रीय तथ्य होगी, और इसमें बसने के लिए पंचायतें होंगी। यह अपने स्वयं के अनाज, सब्जियां और फल, और अपनी खादी का उत्पादन करेगा। इस आधार पर गाँधी जी ने स्वराज एवं आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज पर अपने विचार दिए है।

भारतीय रक्षा नीति के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार है :-

1) 2025 तक रक्षा क्षेत्र में 1,75000 करोड़ों का कारोबार करना जिसमें 35000 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है जो एयरोस्पेस एवं रक्षा सामान एवं सेवाओं से संबंधित है।

2) इसके माध्यम से एक गतिशील मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है जो अपनी गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हो।

3) आयात पर निर्भरता कम करते हुए और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए विकास के माध्यम की पहल करना।

4) रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रंखला का हिस्सा बनना।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

5) एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां भारत अपने आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

तत्कालीन सन्दर्भ में भारतीय रक्षा क्षेत्र में सुधार

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। आत्मनिर्भर भारत के वर्तमान आवाहन ने भारत के आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया है। तत्कालीन समय में पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित ,अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं ,उत्पादन नीतियों और भारत के मेक इन इंडिया की पहल ने स्वदेशी उत्पादों की मांग को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है। भारतीय रक्षा उद्योग मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध उत्पाद मिशन और बाजार के साथ विकसित हुआ है। निर्यात की तत्कालीन सफलताओं से प्रेरित होकर भारत एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी क्षमता को विश्व तक पहुंचाने में अपना प्रयास कर रहा है। कोविड-19 के खिलाफ भारत के प्रयास ने विशेष रुप से विनिर्माण क्षेत्र में किए गए प्रयास ने आत्मनिर्भरता की अवधारणा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। यहां तक कि जब वायरस का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इसने भारत को एक अवसर प्रदान किया जिसके माध्यम से भारत को विश्वस्तरीय रक्षा विनिर्माण हब के रूप में उभरने वाले दीर्घ लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त क्षण भी प्रस्तुत किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2001 में निजी क्षेत्र के लिए अपने दरवाजे खोलें जिससे उपकरण निर्माण संगठनों में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिली। 2002 में रक्षा मंत्रालय ने नई खरीद प्रबंधन संरचनाओं और प्रणालियों को स्थापित करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया को संशोधित किया। सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति में 2016 तक कई एक के बाद एक संशोधन हुए। मार्च 2020 में इस नीति में एक और संशोधन का प्रस्ताव दिया और जुलाई में इसमे संसोधन के प्रयास किये गए। यह संशोधन रक्षा के क्षेत्र में भारत की मेक इन इंडिया की पहल को प्रस्तुत करता है और खरीद प्रक्रिया को तेज करने का लक्ष्य रखती है । यह नीति स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं पर आधारित है। इसके अंतर्गत उन सुधारों को भी शामिल किया है जिनका उद्देश्य भारतीय उद्योगों की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हुए एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करना है। इस नीति में शामिल प्रमुख श्रेणियों में रक्षा खरीद, पूंजी अधिग्रहण आदि शामिल हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), रक्षा मंत्रालय के शोध एवं विकास विंग ने अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के साथ भारत को सशक्त बनाया। एक मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार के माध्यम से सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीआरडीओ द्वारा अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों / प्लेटफार्मों / उपकरणों की एक बड़ी संख्या को डिजाइन और विकसित किया गया है। सामरिक प्रणालियों और प्लेटफार्मों का विकास और उत्पादन जैसे अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की श्रृंखला; तेजस लड़ाकू विमान; पिनाका-मल्टी-बैरल रॉकेट लांचर; आकाश-वायु रक्षा प्रणाली; रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला; धनुष-तोपखाने की बंदूक; अर्जुन-मुख्य युद्धक टैंक आदि ने भारत की सैन्य शक्ति में एक अद्वितीय छलांग दी है, जिससे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने इनहाउस डिज़ाइन विंग और स्वदेश निदेशालय के माध्यम से भी भारत में डिजाइन और उत्पादन क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एयरोस्पेस और नेवल शिपबिल्डिंग उद्योग सहित रक्षा उद्योग का आकार वर्तमान में लगभग 80,000 करोड़ रुपये (2018-20) का अनुमान है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जहां सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 63,000 करोड़ रुपये है, वहीं निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वर्षों में 17,000 करोड़ रुपये हो गई है।

रक्षा क्षेत्र में कुछ प्रमुख सार्वजानिक कंपनी है जो स्वदेशी नीति को बढ़ावा देती है जिनमे प्रमुख है ,एयरोस्पेस में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) जैसे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) , भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL), भूमि प्रणालियों में आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) रक्षा उत्पादन के आधार रहे हैं एवं देश में पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रम अपने स्वयं के शोध एवं विकास के साथ-साथ डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास के अहम भूमिका निभाते है । निजी क्षेत्र में कई इंजीनियरिंग की बड़ी कंपनियों ने विविधता लाई है और रक्षा क्षेत्र में शामिल हुई हैं। रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए अब तक 460 से अधिक लाइसेंस निजी कंपनियों को जारी किए गए हैं।

फाइनेंसियल एक्सप्रेस के अनुसार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाया। राजनाथ सिंह के अनुसार रक्षा मंत्रालय में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके द्वारा रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। रक्षामंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने 101 आइटम्स की लिस्ट तैयार की है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगेगा। इस लिस्ट में सामान्य वस्तुओ के अलावा कुछ विशेष टेक्नोलॉजी हथियार सिस्टम भी शामिल हैं। एक नकारात्मक आर्म्स लिस्ट तैयार हुई है जिसके तहत कुछ हथियार सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर बैन लगाया जाएगा जिससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाया जा सके। यह लिस्ट सेना की आवश्यकता के हिसाब से समय-समय पर बदलती रहेगी। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक बड़ा एवं निर्णायक कदम है। इस कदम से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन का मौका मिलेगा। यह निर्णय भविष्य में गोला बारूद और रक्षा उत्पादों के निर्माण की भारतीय उद्योग की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ सामान्य वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHs, रडार और कई अन्य सामान। रक्षामंत्री के अनुसार ऐसे उत्पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं द्वारा अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच अनुमानित 3.5 लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 वर्ष में घरेलू उद्योगों को 4 लाख करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। रक्षा मंत्री के अनुसार अगले 6 से 7 साल में इनमें से लगभग 1,30,000 करोड़ रुपये के उत्पाद सेना और वायुसेना के लिए अनुमानित हैं, जबकि नौसेना की ओर से इसमें लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये उत्पादों का अनुमान जताया गया है।

टाइम्स नाउ के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का दौरा किया और भारतीय सेना को अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (MK-1A) सौंपें। अर्जुन टैंक MK-1A को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है, जो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। यह स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह न सिर्फ मेक इन इंडिया की तरफ सकारात्मक कदम है साथ ही यह भारत के पड़ोसी देश के साथ जो सुरक्षा चुनोतियो को लेकर तनाव एवं संघर्ष है उसका मुकाबला करने में सक्षम है।

स्वदेशी रक्षा विनिर्माण: चुनौतियां एवं सुझाव

भारत के पडोसी देश पाकिस्तान एवं चीन के साथ सुरक्षा चुनौतियों की बढ़ती जटिलता और तनाव की वजह से आर्थिक ,सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए भारत को मजबूत रक्षा क्षमताओं की आवश्यकता है। इसके अनुसरण में, पिछले एक दशक में, भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के आयातकों में से एक रहा है। वैश्विक हथियारों के आयात का लगभग 12% रहा है। हालांकि हथियारों, पुर्जों और गोला-बारूद के लिए 60-70% आयात निर्भरता के कारण सैन्य संकटों के दौरान कमजोरियां पैदा होती हैं। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत कई उपायों की घोषणा की है।हालांकि ये कदम सही दिशा में हैं, लेकिन भारत में रक्षा विनिर्माण में वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के समक्ष कुछ चुनौतियां भी है जिन्हे दूर किया जाना चाहिए।

बहुत ज्यादा देरी: पिछले पांच वर्षों में, भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी प्रावधान के हस्तांतरण के साथ 200 से अधिक रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनकी कीमत लगभग 4 ट्रिलियन रुपये है, लेकिन अधिकांश अभी भी प्रसंस्करण के अपेक्षाकृत शुरुआती चरणों में हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रेरित: भारत में दुनिया की शीर्ष 100 सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों में चार कंपनियां (भारतीय आयुध कारखानों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) हैं। इन कंपनियों के सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं और घरेलू आयुध मांग के थोक के लिए जिम्मेदार हैं। सरकारें आमतौर पर 'मेक इन इंडिया' के बावजूद निजी क्षेत्र में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू) को विशेषाधिकार देती हैं। अतार्थ रक्षा क्षेत्र में अभी भी प्रमुख भूमिका सार्वजानिक उद्यमों की है।

आधुनिक टेक्नोलॉजीज का अभाव: महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में खराब डिजाइन क्षमता, आर एंड डी में अपर्याप्त निवेश और प्रमुख उप प्रणालियों और घटकों के निर्माण में असमर्थता स्वदेशी विनिर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। आरएंडडी प्रतिष्ठान, उत्पादन एजेंसियों (सार्वजनिक या निजी) और अंतिम-उपयोगकर्ता के बीच संबंध और समन्वय बेहद कमजोर हैं।

लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड: एक मैन्युफैक्चरिंग बेस का निर्माण कैपिटल और टेक्नॉलॉजी-इंटेंसिव होता है और इसमें लॉन्ग जेस्चर पीरियड होता है। क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर तक पहुंचने के लिए एक कारखाने के लिए, यह पांच से 10 के बीच कहीं भी 15 साल तक ले सकता है और जब तक एक इकाई उत्पादन शुरू करती है, तब तक निम्न में से कोई भी विकास हो सकता है: प्राथमिकताओं में पूर्ण परिवर्तन को शामिल करते हुए रणनीति में परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नया उन्नत रडार सिस्टम खरीदना अधिक टैंक या बख्तरबंद वाहनों को जोड़ने के बजाय एक उच्च प्राथमिकता

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्राप्त कर सकता है। नई प्रौद्योगिकियां उन उत्पादों को पुराना बना सकती हैं जो शत्रु के अधिग्रहण के साथ मेल नहीं खा सकते हैं।

विनिर्माण पर्यावरण का अभाव: इसके अलावा, कठोर श्रम कानूनों, अनुपालन बोझ और कौशल की कमी से संबंधित मुद्दे, रक्षा में स्वदेशी विनिर्माण के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके कारण, भारत रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं कर पाया है।

समन्वय की कमी: रक्षा मंत्रालय और औद्योगिक संवर्धन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र को ओवरलैप करना भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को प्रभावित करता है।

सुझाव

पहला सुझाव यह है कि निजी उद्यमी क्षेत्रो को भी सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर भागीदारी का मौका प्राप्त हो। **दूसरा** जिस तरह सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत में सैनिक स्कूल चलाए जाते हैं उसी तरह रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राथमिक स्तर से ही रक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखकर जगह-जगह विद्यालय खोलने की आवश्यकता है जहां पर रक्षा तकनीक से संबंधित ही शिक्षा प्रदान कराई जाये । **तीसरा** शोधार्थियों को रक्षा क्षेत्र से संबंधित शोध करने हेतु सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता है जिससे शोधार्थी रक्षा क्षेत्र में शोध करने हेतु आगे आएं व भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। **चौथा** रक्षा क्षेत्र से संबंधित सभी वैज्ञानिकों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं व आर्थिक सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे भारत ब्रेन ड्रेन से बच सके और रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

निष्कर्ष

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नव नियुक्ति से यह एक त्रिसेवा कोण के माध्यम से रक्षा अधिग्रहण की जांच कर सकता है और इससे देरी से बचा जा सकता है व रक्षा खरीद प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। रक्षा क्षेत्र एवं राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक विकास की पूर्वगामी है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत कई सुधार हुए जिसने स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दिया जिसमे प्रमुख है कि स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी तथा देश को उत्पादन के मामले में स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में अर्जुन टैंक सेना को सौपा जो स्वदेशी उद्योग द्वारा निर्मित है। लगातार बॉर्डर पर पडोसी देशो पाकिस्तान और चीन की ओर से बढ़ते तनाव की वजह से स्वदेशी को सशक्त बनाना भी अनिवार्य है। हमे बुलेट टू वॉलेट सभी क्षेत्र में विकास करना है। हाल ही में चीन में मोबाइल एप्लीकेशन स्ट्राइक उदहारण है की सिर्फ बॉर्डर पर रहकर ही नहीं बल्कि इन सभी चीजों में प्रतिबन्ध करके भी आप शत्रु के महत्वकांशी हितो को रोक सकते है। वैश्वीकरण में जहा सभी देश जटिल अंतर्निर्भर है एक दूसरे पर, वही भारत का मेक इन इंडिया का प्रयास चुनौतीपूर्ण है क्यूंकि भारत के पास संसाधन की भी सीमितता है। भारत इन सभी चुनौती से सकारात्मक रूप से निपट रहा है और विश्व में विकास का एक विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता रक्षा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

एवं सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में ताकत बढ़ाने से एवं विश्व के साथ काम करने की शर्तें नए सिरे से तैयार करने से बनेगा।

संदर्भ सूची

1) रक्षा मंत्रालय,(2020),भारत सरकार ,रक्षा मंत्रालय "डिफेंस एक्वीजीशन प्रोसीजर 2020 कैपिटल प्रोक्योरमेंट",नई दिल्ली ,2020

2) पाटिल,समीर.(2016),"इंडिया डिफेन्स : टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस",मुंबई ,गेटवे हाउस

3) देसाई ,नीशीथ(2018), "द इंडियन डिफेन्स इंडस्ट्री रेडेफिनिंग फ्रंटियर्स" ,निशीथ देसाई एसोसिएट्स

4) बेहेरा,लक्ष्मण.(2013),"इंडियन डिफेन्स इंडस्ट्री इश्यूज ऑफ़ सेल्फ रिलायंस", इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज & एनेल्सिस

5) नारायण,के,जी.(2019) ," डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजीज : रोड तो नोवेयर और वे टू गो ?"वॉल्यूम 4 ,नंबर 3,जर्नल ऑफ़ डिफेन्स स्टडीज

6) बक्शी,शिवशक्ति (2020) ,"टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत " कमल सन्देश , डॉ मुखर्जी स्मृति न्यास

7) बेहरा,लक्ष्मण(2020),"आत्मनिर्भर इन डिफेन्स टेक्नोलॉजी ",इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिफेन्स स्टडीज एंड एनालिसिस ,नई दिल्ली,10 अगस्त 2020

8) सिद्दीकी,हूमा (2020),"आत्मनिर्भर भारत इन डिफेन्स :द न्यू डीएपी टू फोकस ऑन मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब",द फाइनेंसियल एक्सप्रेस,नई दिल्ली,29 सितम्बर 2020

9) शेखर,सिद्धार्थ(2020),"बिग पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत एस इंडिया परमिटस अप टू 74% एफडीआई इन डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग,टाइम्स नाउ ,नई दिल्ली ,27 अगस्त 2020

10) कौशिक,कृष्ण(2020),"एक्सप्लेन:द नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट फ़ॉर डिफेंस अनाउंस बाय राजनाथ सिंह",द इंडियन एक्सप्रेस,नई दिल्ली,11 अगस्त 2020

11) कर्नाड,भारत(2020),"हाऊ टू गेट आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन",ब्लूमबर्ग क्विंट ओपिनियन,24 अगस्त 2020

12) देसाई,अशोक(2020),"व्यू:द प्रॉब्लम विथ मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान",द इकोनॉमिक्स टाइम्स,नई दिल्ली,15 मई 2020

13) सिद्दीकी,हुमा(2020),"पीएम मोदी बेटस फ़ॉर आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस,सेय इंडिया है कैपिबिलिटी टू बिकम रिलाएबल सप्लायर",फाइनेंसियल एक्सप्रेस,नई दिल्ली,28 अगस्त 2020

14) पांडेय,अतुल(2020),"रीसेंट रिफार्मस इन द इंडियन डिफेंस सेक्टर",फाइनेंसियल एक्सप्रेस,नई दिल्ली,1 जून 2020

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 03, March- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

15) प्रसाद,अ एंड अनंदिता,को(2020),"व्यू: मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर इन द डिफेंस सेक्टर",द इकनोमिक टाइम्स,नई दिल्ली,23 जून 2020